## MATTERS RAISED WITH PERMISSION

### Violation of Constitutional norms in the general elections by certain political parties

**श्री राशिद अल्वी** (आन्ध्र प्रदेश): सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं आज एक बहुत अहम मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। गालिबन आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। पिछली बार 4 अप्रैल, 2007 को जब उत्तर प्रदेश के असेम्बली के चुनाव हो रहे थे, तो एक राजनीतिक दल ने एक बहुत ही भयानक सी0डी0, एक ऐसी सी0डी0 जो उत्तर प्रदेश को आग और खून के अन्दर डुबो सकती थी, एक ऐसी सी0डी0 जो एक समुदाय के जजबात भड़काने का काम कर रही थी, वह सी0डी0 ...**(व्यवधान)**... मैंने किसी राजनीतिक दल का नाम अभी तक नहीं लिया है ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति**: आप बोलते जाइए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री राशिद अल्वी**: इलेक्शन कमिशन के नॉलिज में यह बात आई और इलेक्शन कमिशन ने एक ऑर्डर पास किया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। इलेक्शन कमिशन ने यह ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की जाए। लखनऊ के कोर्ट के अन्दर ...**(व्यवधान)**... सर, भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, जिसके अन्दर * भी शामिल हैं। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के दस बड़े नेताओं के खिलाफ, * के खिलाफ, * के खिलाफ, एफ0आई0आर0 दर्ज हुई ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति**: जो मैम्बर्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनके नाम मत लीजिए। ...**(व्यवधान)**... ये नाम निकाल दीजिए।

**श्री राशिद अल्वी**: इलेक्शन कमिशन ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का सिम्बल सीज़ कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस में एफ0आई0आर0 है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। मैं हाउस के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। एस0एस0पी0, लखनऊ ने इलेक्शन कमिशन को इत्तिला दी है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ चार्ज शीट फाइल हुई। लेकिन, सर, चीफ इलेक्शन कमिशन ने एक बयान में कहा है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने माफी माँग ली है, इसलिए उन्हें माफ कर दिया गया है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस तरीके की सी0डी0 से कुछ लोग सिर्फ सत्ता की लालच में अगर देश को बाँट देना चाहते हैं, धर्म और मजहब के बीच में ...**(व्यवधान)**... तो क्या गारंटी है कि आने वाले चुनाव में वे इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे? ...**(व्यवधान)**... चुनाव आने वाला है। दो महीने के बाद चुनाव होने वाला है। ....(व्यवधान)... सर, मेरा कहना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांग ली है, इसलिए हमने माफ कर दिया, लेकिन दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने यह कहा, जिनके स्टेटमेंट मेरे पास हैं, कि इस तरीके की माफी की हमारे पास कोई इत्तला नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भारतीय जनता पार्टी को कैसे माफी दे दी? यह एक गंभीर मामला है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, I am on a point of order.

**श्री उपसभापति**: अल्वी जी, आप बैठिए, आपका समय हो गया।

**श्री राशिद अल्वी**: सर, मेरा मुतालवा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को सीज होना चाहिए, ताकि इस सेकुलर देश के अंदर ऐसा फिर न हो। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am not challenging the authority of the Chair. You have permitted him. But the point is very simple, Sir. Zero Hour mentions are normally raised in this House on

*Not recorded.

matters of urgent public importance. Reports about whatever the hon. Member has just aired in this House about Election Commissioners and others are not available with me. If you want to discuss that matter, let Government bring out the report. ...*(Interruptions)*...

श्री **उपसभापति**: नहीं, नहीं। आप छोड़िए। ..**(व्यवधान)**.. अल्वी साहब, आप बैठिए। Nothing will go on record. ...**(व्यवधान)**... You have stated ...*(Interruptions)*... आपने अपनी बात कह दी, आपकी बात हो गई। आप बैठिए।

SHRI S.S. AHLUWALIA: We are ready to discuss even Navin Chawla's case. Let us discuss that matter here. Let us discuss the whole affair of the Election Commissioners. What do you have to say? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Chandran Pillai ...*(Interruptions)*.. आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Why have you allowed him?

**श्री उपसभापति**: यह क्या है? आपका सवाल नहीं है। ...**(व्यवधान)**... He is asking me why I have allowed you to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let us have that report and letter written by the Chief Election Commissioner. ...*(Interruptions)*... Let us discuss the matter here. ...*(Interruptions)*... How does he have access to the letter written by the Chief Election Commissioner?...*(Interruptions)*... Who has given you that? Let us discuss the matter. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): The matter has been published in all the newspapers. ...*(Interruptions)*... Now you are talking about the letter. How can you discuss it? You are talking about. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, please. Mr. Ahluwalia, you have said whatever you wanted to say. Please, take your seat. Shri Chandran Pillai.

**Proposal for selling of shares of the Cochin Shipyard Ltd.**

SHRI K. CHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, this is regarding the proposed disinvestment of Cochin Shipyard. The Cochin Shipyard was incorporated in the year 1972 as a fully owned Government of India Company. The Cochin Shipyard Company came into being after a State-wide struggle by late A.K. Gopalan, who was then a Member of the Lok Sabha. The Cochin Shipyard can build ships up to 1,10,000 dwt and repair ships upto 1,25,000 dwt. The yard has delivered two of India's largest double-hull tankers of 95,000 dwt each. The Cochin Shipyard Limited has acquired ship building orders from internationally renowned companies from Europe and Middle East and it is nominated to build the country's first indigenous air defence ship. I would like to bring to the Government's attention the resentment growing among the workers of Cochin